शिकायत | भोपाल तक पहुंची शिकायत, उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज

डिंडोरी नगर परिषद में अनियमितताओं का विस्फोट

डिंडोरी, नवभारत 13 फरवरी। नगर परिषद डिंडोरी में कथित प्रशासनिक, पर्यावरणीय और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब राजधानी तक पहुंच गया है। 12 फरवरी को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के आयुक्त को समेकित शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

शिकायत अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं डिंडोरी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 6 निवासी रोहित कांसकर द्वारा की गई है। बता दें कि जिले के आला अधिकारियों के समक्ष पूर्व में अनेकों शिकायतें दिए जाने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर शिकायतकर्ता को भोपाल का रुख करना पड़ा।

जलाशय से लेकर टेंडर तक आरोपों की लंबी फेहरिस्त

शिकायत में वार्ड क्रमांक 13 स्थित शासकीय जलाशय में सीवर लाइन डाले जाने, अवैध भराव, बाउंड्री से छेड़छाड़, 30 मीटर दायरे में निर्माण, जल संसाधन विभाग की अनुमति के बिना कार्य और सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपये आहरित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि जलाशय क्षेत्र में अवैध कब्जा कर पक्का मकान तक बना लिया गया, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। वार्ड 4 मुर्गी मार्केट में धार्मिक स्थल के सामने अवैध कब्जे, अलाव मद की राशि निकासी के बावजूद लकड़ी वितरण नहीं होने और अन्य मदों में कथित गड़बड़ियों का भी उल्लेख है। वार्ड 7 मेकलसुता आश्रम प्रकरण में स्टे आदेश और तहसीलदार के निर्देशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने का भी आरोप लगाया गया है।

कचरा प्रबंधन और डिवाइडर निर्माण पर सवाल

दो वर्षों तक बिना बीमा कचरा वाहनों के संचालन, कचरा निस्तारण स्थल 8 किमी दूर होने के बावजूद वार्ड 10 में कचरा डालने और जलाने से वाहन में आग लगने की घटना का जिक्र शिकायत में है। आरोप है कि संबंधित वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने वाहन स्वामित्व से इंकार किया।डिवाइडर निर्माण में त्रुटिपूर्ण डीपीआर, आधा निर्माण कर बाद में तोड़फोड़, और पेड़ों की कटाई का भी मामला उठाया गया है।

टेंडर, भुगतान और होर्डिंग में हेरफेर

शिकायत में आरोप है कि फ्लेक्स टेंडर को नियमविरुद्ध रोका गया, 10-10 पैसे जैसी अव्यवहारिक दरें तय कर मनचाही फर्म को लाभ पहुंचाया गया तथा 1 लाख से कम भुगतान कर वित्तीय नियमों से बचने की कोशिश की गई। होडिंग अनुमति में पारदर्शिता की कमी, 2.20 लाख जमा कर रसीद काटने के बावजूद प्रक्रिया स्पष्ट न होना भी जांच के दायरे में लाया गया है।

शिकायतकर्ता पर दबाव

शिकायत पत्र में आरटीआई आवेदन में पृष्ठ संख्या गलत बताने, निर्धारित 2 प्रति पृष्ठ के स्थान पर 3 रुपये वसूलने तथा वीडियो सूचना देने में टालमटोल का भी उल्लेख है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जनहित में आवाज उठाने पर शिकायतकर्ता को धमकियां दी गईं और पर्व-त्यौहार के होर्डिंग तोड़े गए, जिनके वीडियो एवं फोटो साक्ष्य संलग्न बताए गए हैं।

उच्च स्तरीय जांच और सुरक्षा की मांग

आवेदकों ने स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने, वित्तीय एवं तकनीकी ऑडिट कराने, दोषी अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों पर विधिसम्मत कार्रवाई, शासकीय भूमि व जलाशय की पुनर्स्थापना तथा शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

अब गेंद शासन के पाले में

मामला सीधे भोपाल स्थित संचालनालय तक पहुंच चुका है। यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो न केवल नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर बड़ा खुलासा हो सकता है, बल्कि जवाबदेही की नई मिसाल भी कायम हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन-प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर कितनी तत्परता दिखाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान में तेजी

डिंडोरी। विगत दिवस सीईओ जिला पंचायत डिंडोरी द्वारा जानकारी दी गई है कि जिले की ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर पर संचालित मनरेगा निर्माण कार्यों की लंबित मजदूरी का भुगतान भारत सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब तक लगभग 4.34 करोड़ की श्रमिक मजदूरी का सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। शेष लंबित भुगतान की प्रक्रिया भी शासन स्तर पर निरंतर जारी है। प्रशासन द्वारा नियमित मॉनिटरिंग करते हुए भुगतान प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, ताकि सभी श्रमिकों को समय पर उनका पारिश्रमिक मिल सके।

ऑटो-आर्टिका की टक्कर, 10 घायल

दो जबलपुर रेफर, उमरिया-ताला मार्ग पर भीषण सड़क हादसा

नवभारत उमरिया 13 फरवरी। जिला मुख्यालय से होकर ताला की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे में सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास शुक्रवार की रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर किया गया।

बताया गया है कि आर्टिका कार क्रमांक एमपी 54 जेडबी 7435 और ऑटो टैक्सी के बीच सीधी टक्कर हुई है, जिसमे सवार 10 लोग घायल हुए है। घायल लीला बाई और सूभरन सिंह ने

बताया कि वे लोग ग्राम बरतराई से चंदिया थाना अंतर्गत मझौली जा रहे थे तभी यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रति ट्रक 3 क्विंटल धान की शॉर्टेज

आपत्ति के बाद वेयर हाउस संचालक को नोटिस

नवभारत उमरिया 13 फरवरी। धान खरीदी केंद्रों से वेयर हाउस में जमा होने वाली धान में से प्रति ट्रक लगभग 3 क्विटल की शॉर्टेज के चलते खरीदी केंद्र प्रभारी व प्रबंधकों ने आपत्ति जाहिर की थी। खरीदी केंद्र प्रभारियों ने बताया कि ज्यादा शॉर्टेज होने के चलते पूरी जवाबदारी हम पर थोपी जा रही है। वेयर हाउस के संचालक पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से किए जाने पर आनन फानन में नापतौल विभाग ने पहुंचकर मामले में पर्दा डालते हुए धर्म कांटे को दुरूस्त कर दिया था। इससे जो क्षति खरीदी केंद्र प्रभारी एवं प्रबंधकों को हुई उसकी भरपाई के लिए कोई ठोस कदम नही उठाए गए। इसे लेकर फिर से शिकायत की गई तो प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

जांच में पायी गई धर्मकांटे में गड़बड़ी व अनियमितताएं

मिली जानकारी में बताया गया कि धान उपार्जन समिति प्रबंधकों से प्राप्त शिकायत पर वेयर हाउस गोदाम पाली में धर्मकांटे में गडबडी एवं धान के स्टॉक के वजन में अंतर आने की किसानों द्वारा की गई शिकायत के बाद बीते 3 जनवरी को पूरे मामले की जांच की गई। जहां जांच के दौरान तौल में गड़बड़ी के साथ अनियमितता पायी गई। इसके बाद वेयर हाउस के संचालक एवं वेयर हाउस केयर टेकर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी का उत्तर चाहा गया है एवं प्रकरण में निमयानुसार कार्रवाई प्रचलित है।

10 लाख का खेल, करोड़ों के बिल!

प्रशासनिक गलियारों में मचा हुआ है घमासान, सीईओ-एडीएम में ठनी

नवभारत उमरिया 13 फरवरी। जिले में पिछले माह आयोजित हुई राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता अब खेल नहीं, बल्कि खतरनाक खेल में तब्दील हो गई है। प्रतियोगिता के नाम पर पेश किए गए अनाप-शनाप और फर्जी बिलों को ठिकाने लगाने के लिए प्रशासनिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है।

सूत्रों की माने तो जिला पंचायत सीईओ और प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी अभय सिंह ओहरिया इन बिलों को पास कराने के नियमों की ढाल लिए बैठे अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेनगुप्ता ने भ्रष्टाचार की फाइल पर ब्रेक लगा दिया है। भ्रष्टाचार की इस नूराकुश्ती ने उस उस समय तूल पकड़ लिया जब कलेक्टर की मौजूदगी में ही सीईओ और अपर कलेक्टर के बीच जमकर तनातनी और गर्मागर्मी हो गई।

सीईओ का पारा पहुंचा सातवें आसमान पर

69वीं राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता उमरिया में 01 से 6 दिसम्बर 2025 तक आयोजित की गई थी। आयोजक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल एवं स्कूल शिक्षा विभाग उमरिया समिति की रिपोर्ट के बिलों को कचरा समझकर वापस कर दिया, तो सीईओ का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जिले के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब दो वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार के बिलों को लेकर आमने-सामने आ गए हों।

10 लाख का काम, करोड़ों की बंदरबांट

इस महा-घोटाले में अब सत्ताधारी दल भाजपा ने भी एंट्री मार दी है। वरिष्ठ नेता मिथिलेश पयासी और जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो प्रतियोगिता 10 लाख में शानदार तरीके से हो सकती थी, उसके लिए करोड़ों के फर्जी बिल लगाना शासन के साथ गद्दारी है। भाजपा नेताओं ने इस सरकारी डकैती की शिकायत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेज दी है। उन्होंने मांग की है कि जब तक पाई-पाई की जांच न हो जाए, एक भी रुपया भुगतान नही किया जाये।

भोपाल को हराकर मुंबई सेमीफाइनल में

सृजन अठावले ने जड़ा शतक

नवभारत उमरिया 13 फरवरी। स्थानीय अमर शहीद स्टेडियम में आयोजित 27वें अखिल भारतीय पैराडाइज गोल्ड कप क्रिकेट महाकुंभ के अंतिम क्वार्टर फाइनल में मुंबई और भोपाल के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30-30 ओवरों के मैच में 28.4 ओवरों में सभी विकेट खोकर 251 रन बनाए। सृजन अठावले ने टूर्नामेंट का पहला शतक लगाते हुए 78 गेंदों में शानदार 100 रन बनाए। अजीत राय ने 50 रन की तेजतर्रार पारी खेली, जबकि सौरभ ने मात्र 12 गेंदों में विस्फोटक 41 रन बनाकर पारी को और मजबूती प्रदान की। भोपाल की ओर से प्रताप सिंह, देवव और किनसुख ने 2-2 विकेट लिए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि रश्मि सिंह ने मैदान पर पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के खेल महाकुंभ जिले के युवाओं को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं।

खनिज माफियाओं पर चला प्रशासन का हंटर

रेत और गिट्टी के अवैध खेल में लगे तीन वाहन जब्त, हड़कंप

चिल्हारी नवभारत 13 फरवरी। जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खजाने को चूना लगाने वाले माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर के कड़े निर्देशों के बाद खनिज विभाग की टीम ने सडकों पर उतरकर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे दो भारी डंपर और एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया।

खनिज विभाग की टीम ने ताला-मानपुर रोड पर घेराबंदी कर अवैध रेत से लदे 1 हाईवा को पकड़ा, जिसका मालिक दमोह का हैं।मालिक का नाम भरत लाल कुर्मी बताया जा रहा है। वहीं,

कटनी के राजेश कुमार साहू का डंपर भी अवैध रेत ढोते हुए गिरफ्त में आया। इतना ही नहीं, बिना नंबर के एक ट्रैक्टर को भी गिट्टी की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

दबाव बनाने की कोशिशें नाकाम

प्रभारी अधिकारी डॉ. विद्याकांत तिवारी और उनकी टीम की इस अचानक कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हडकंप मच गया है। सहायक खनि अधिकारी दिवाकर चतुर्वेदी ने साफ कर दिया है कि म.प्र. खनिज नियम 2022 के तहत इन सभी पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा अवैध परिवहन की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। प्रशासन के इस तेवर ने साफ कर दिया है कि जिले की धरती को खोदकर अपनी जेबें भरने वालों की अब खैर नहीं। सघन जांच जारी है और कई बड़े नाम अभी रडार पर है।

एनएच 30 पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक

नारायणगंज। नेशनल हाईवे 30 पर नारायणगंज मैली चौराहे और बालाई के बीच एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। दिल्ली से रायपुर की ओर जा रहा एक ट्रक क्रमांक एमपी 07 डी 9858 अनियंत्रित होकर हाईवे मार्ग में एक वाहन को बचाने के चक्कर में पलट गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक चालक देवेंद्र सिंह यादव निवासी मुरैना ने बताया कि वह दिल्ली से माल लोड कर रायपुर की ओर जा रहा था। मैली चौराहे और बालाई पुल के पास अचानक सामने से एक कार आ गई, जिसे बचाने के फेर में ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में चालक अकेला ही सवार था। गनीमत रही कि इस हादसे में चालक और सामने आ रही कार को कोई हानि नहीं पहुंची। सभी बाल-बाल बच गए।

जवानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है बीमा : शर्मा

थाना करंजिया में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

करंजिया,नवभारत 13 फरवरी। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदित एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत थाना करंजिया में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत पुलिस जवानों को गंभीर दुर्घटनाओं एवं आकस्मिक परिस्थितियों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम में एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस के एरिया हेड मनीष शर्मा ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान पुलिस बल को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह बीमा योजना जवानों एवं उनके परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। उन्होंने बीमा कवर, क्लेम प्रक्रिया एवं अन्य लाभों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

पुलिस जवानों के हित में महत्वपूर्ण कदम

कार्यशाला में थाना प्रभारी नरेंद्र पॉल सहित सउनि तिलगाम, प्रआर जगन मार्को, मप्रआर संगीता उइके, रामनंदन सनौड़िया एवं शिवपाल कौरव उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने योजना में रुचि दिखाते हुए इसे पुलिस परिवार के लिए उपयोगी बताया। अंत में थाना प्रभारी ने इस पहल को पुलिस जवानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए आभार व्यक्त किया।

डिजिटल इंडिया के दावों की निकली हवा

उमरिया में सर्वर पूरी तरह ठप, मजदूरी छोड़कर दुकानों के चक्कर काट रहे ग्रामीण

नवभारत उमरिया 13 फरवरी। सरकारी तंत्र की लापरवाही और तकनीकी खामियों ने उमरिया जिले के हजारों गरीबों के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से जिलेभर की उचित मूल्य की दुकानों का सर्वर पूरी तरह ठप पड़ा है। आलम यह है कि दूर-दराज से आने वाले उपभोक्ता सुबह से शाम तक दुकानों के बाहर भूखे-प्यासे खड़े रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मशीन पर सर्वर डाउन का अंगूठा दिखाकर वापस भेज दिया जाता है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब करकेली स्थित आदिम जाति मर्यादित सहकारिता दुकान पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे

गया। ग्रामीणों ने वहां जमकर हंगामा किया।

राशन के लिए भटक रहे ग्रामीण

कडकड़ाती धूप और काम के सीजन में ग्रामीण अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोडकर राशन के लिए भटक रहे हैं। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी गरीबों को अनाज का एक दाना नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बार-बार बुलाया जाता है, जिससे उनका आर्थिक और मानसिक उत्पीडन हो रहा है। जिलेभर में फैली इस अव्यवस्था ने सबका साथ-सबका विकास के नारों की पोल खोलकर रख दी है। कहना है कि मशीन का सर्वर हैदराबाद से संचालित होता है और फिंगरप्रिंट न आने के कारण वे अनाज नहीं बांट पा रहे हैं। गरीब की भूख सर्वर के ठीक होने का इंतजार कर रही है।

जिम्मेदारों की कॉल बता रही नॉट रिचेबल

हैरानी की बात तो यह है कि जब इस गंभीर संकट पर जिला खाद्य अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो वे उपलब्ध नहीं हुए। वहीं, विभागीय टेक्निकल इंजीनियर का तर्क है कि समस्या पूरे मध्य प्रदेश में है। यह जवाब उस जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है, जहाँ गरीब का बच्चा घर में भूखा सो रहा हो। अगर समस्या प्रदेश स्तर पर है, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, क्या जनता की परेशानी से कोई लेना-देना ही नहीं है। अधिकारियों के जल्द चालू हो जाएगी वाले रटे-रटाए जवाबों से जनता का पेट नहीं भरने वाला। सवाल यह है कि डिजिटल व्यवस्था के नाम गरीबों को इस तरह प्रताड़ित करना कब बंद होगा।

युवा राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका : सरपंच

करौंदी में एनएसएस का सात दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ

शहपुरा नवभारत 13 फरवरी। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत करौंदी में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का सात दिवसीय विशेष शिविर 10 फरवरी से प्रारंभ होकर 16 फरवरीतक आयोजित किया जा रहा है।

भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्ध इस शिविर का आयोजन 'मेरा युवा भारत एवं डिजिटल साक्षरता के लिए युवा' थीम पर किया जा रहा है। शिविर का संचालन संभागीय समन्वयक डॉ. शोभाराम मेहरा, जिला संगठक डॉ. पीसी उइके एवं शास. आदर्श महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. स्वीटी यादव के निर्देशन में तथा एनएसएस कार्यक्रम प्रभारी डॉ. एलएन साहू के नेतृत्व में किया जा रहा है।

हितग्राही योजनाओं की दी जाएगी जानकारी-शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत करौंदी की सरपंच दुर्गा बाई एवं प्राचार्य डॉ. स्वीटी यादव द्वारा मां सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पूजन तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उद्घाटन अवसर पर वक्ताओं ने युवाओं से समाज सेवा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। सात दिवसीय शिविर के अंतर्गत स्वयंसेवक ग्रामीणों को मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न हितग्राही योजनाओं की जानकारी घर-घर जाकर दे रहे हैं। कार्यक्रम में महाविद्यालय के श्रीराम ठाकुर, डॉ. नेहा चौहान, डॉ. वीना शिवहरे, भागवत सिंह धुर्वे, पीएस वरकड़े, डॉ. परमेश साकेत, टीपी साहू, डॉ. अनिल झारिया, डॉ. राजू रैदास, डॉ. राजेश तिवारी, मधुर मरावी, कृति जैन, आकांक्षा कुशराम एवं अभिषेक पटेल सहित समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

बेनकाब | मानपुर परिक्षेत्र में संवेदनहीनता और झूठे वादों का शर्मनाक मामला उजागर

गरीब की 9 महीने की मजदूरी डकार गया वन विभाग

चिल्हारी नवभारत 13 फरवरी। जिले के मानपुर परिक्षेत्र में वन विभाग की संवेदनहीनता और झूठे वादों का एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने सरकारी तंत्र के मानवीय चेहरे को बेनकाब कर दिया है।

एक तरफ जहां सरकार आदिवासियों के कल्याण के ढोल पीटती है, वहीं दूसरी ओर ग्राम बिजौरी के एक पीड़ित पिता को अपने बेटे की मौत के बदले मिले आश्वासन को पाने के लिए भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बाघ के हमले में बेटे को खोने वाले महिपाल बैगा के साथ वन विभाग ने न केवल वादाखिलाफी की, बल्कि 9 महीने तक काम कराकर उसे पाई-पाई के लिए मोहताज कर दिया है।

बेटे की मौत पर मिला था नौकरी का झुनझुना

मामले की जड़ें वर्ष 2023 की उस दर्दनाक घटना से जुड़ी हैं, जब महिपाल बैगा के पुत्र अनुज बैगा को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। उस समय आक्रोश को शांत करने और सहानुभूति बटोरने के लिए वन विभाग के आला अफसरों ने पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया था कि महिपाल और उसके भाई सुखलाल बैगा को वन विभाग में स्थायी रूप से चौकीदार के पद पर तैनात किया जाएगा, लेकिन आज हालात यह हैं कि विभाग अपनी ही बातों से पलटता नजर आ रहा है।

आदिवासी काट रहा दफ्तरों के चक्कर

आश्वासन के बाद महिपाल बैगा को बडखेरा बीट में चौकीदार के पद पर तैनात तो कर दिया गया, लेकिन विडंबना देखिए कि विभाग ने उनसे 9 महीने तक हाड़-तोड़ मेहनत कराई और जब मजदूरी देने की बारी आई, तो हाथ खड़े कर लिए। वर्ष 2024 के दौरान किए गए इस कार्य का वेतन आज तक महिपाल को

नहीं मिला है। एक गरीब आदिवासी, जिसने अपना बच्चा खोया, अब अपने पसीने की कमाई के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सवाल यह उठता है कि वया वन विभाग के बजट में इस गरीब की मजदूरी के पैसे नहीं थे या फिर अफसरों की फाइलों में यह राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।

अब भाई को नौकरी देने से कर दिया इंकार

पीड़ित महिपाल बैगा का आरोप है कि पूर्व में विभाग ने दोनों भाइयों (महिपाल और सुखलाल) को नौकरी देने का बादा किया से मुकरते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ एक को ही काम मिलेगा। यह सीधे तौर पर था। अब अधिकारी अपनी जुबान एक आदिवासी परिवार के साथ धोखाधड़ी है। क्या प्रशासन तब तक सोता रहता है जब तक कोई गरीब बेमौत प्रति नहीं मर जाता और मरने के बाद किए गए वादे क्या सिर्फ कागजी खानापूर्ति के लिए होते हैं।

कलेक्टर और डीएफओ की चौखट पर न्याय की गुहार

पीड़ित ने अब वनमंडलाधिकारी उमरिया को पत्र लिखकर अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले भी मानपुर परिक्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर परिणाम शून्य रहा। पीड़ित का कहना है कि यदि उसे और उसके भाई को स्थायी नियुक्ति नहीं मिली और 9 माह का बकाया वेतन तत्काल जारी नहीं किया गया, तो वह उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इस पत्र के सार्वजनिक होते ही वन विभाग के गलियारों में खलबली मच गई है। सूत्र बताते हैं कि आला अफसर अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर 9 महीने तक एक गरीब की मजदूरी क्यों रोकी गई।